



ACHIEVE-2023

All India Open Mock Test Mains-2023

मॉडल उत्तर सामान्य अध्ययन (GS-III & IV)

ACHIEVE-02



641, प्रथम तल,
मुखर्जी नगर,
दिल्ली

21, पूसा रोड,
करोल बाग,
नई दिल्ली

13/15, ताशकंद मार्ग,
निकट पत्रिका चौराहा,
सिविल लाइन्स, प्रयागराज

1st & 2nd Floor, No-47/CC,
बर्लिंगटन आर्केड मॉल,
विधानसभा मार्ग, लखनऊ

प्लॉट नंबर-45 व 45-A
हर्ष टावर-2, मेन टॉक रोड,
वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर

1

दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 :: ई-मेल: help@groupdrishti.in :: वेबसाइट: www.drishtiIAS.com

Copyright – Drishti The Vision Foundation



1. समावेशी, निम्न-उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास एजेंडा अपनाने से भारत के घरेलू सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत में जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग के संदर्भ में चर्चा कीजिये।

(150 शब्द) 10

Adopting an inclusive, low-emission and climate-resilient growth agenda would significantly boost the effectiveness of India's domestic public spending. Discuss in the context of climate-responsive budgeting in India.

(150 Words) 10

उत्तर: भारत एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहाँ आर्थिक विकास को, पर्यावरणीय चिंताओं खासकर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, संतुलित किये जाने की आवश्यकता है। जलवायु बजटिंग उन व्ययों की पहचान, वर्गीकरण और वर्गीकरण को सक्षम बनाता है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। इसके बढ़ते महत्व को 2017 में पेरिस में 'द वन प्लैनेट समिट' के दौरान घोषित 'Paris Collaborative on Green Budgeting' के गठन के संदर्भ में समझा जा सकता है।

एक वैश्विक अनिवार्यता के रूप में जलवायु परिवर्तन

● **संयुक्त राष्ट्र और UNFCCC का दृष्टिकोण:**

- संयुक्त राष्ट्र और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) जलवायु परिवर्तन की वैश्विक तात्कालिकता पर जोर देता है।
 - इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जलवायु परिवर्तन से निपटने में देश की जिम्मेदारी को रेखांकित करती है।

घरेलू सार्वजनिक व्यय और जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग:

- विश्व बैंक जलवायु उद्देश्यों के साथ घरेलू सार्वजनिक व्यय को सुसंगत बनाने के महत्व को रेखांकित करता है।
 - जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग में बजट योजना, आवंटन और निष्पादन के हर पहलू में जलवायु संबंधी विचारों को शामिल करना शामिल है।

जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग के लाभ

● **अनुकूलित संसाधन आवंटन:**

- नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों और परियोजनाओं की पहचान करके संसाधनों के विवेकपूर्ण आवंटन की सुविधा प्रदान करती है।
 - यह दृष्टिकोण निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकता है और लागत-प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

● **विकास में समावेशिता:**

- जलवायु-अनुकूल परियोजनाएँ अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर असंगत रूप से सकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
 - समावेशी, जलवायु-लचीले विकास को प्राथमिकता देने से जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को भी कम किया जा सकता है।

● **रणनीतिक योजना:**

- नीति आयोग जलवायु लक्ष्यों को शामिल करने की वकालत करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जलवायु लचीलापन देश के विकास एजेंडे में जटिल रूप से बुना गया है।

● **क्षमता वृद्धि:**

- जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नीति आयोग विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों के लिए व्यापक क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों की सिफारिश करता है।

● **नवीकरणीय ऊर्जा निवेश:**

- जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग द्वारा समर्थित नवीकरणीय ऊर्जा में भारत के रणनीतिक निवेश ने न केवल उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दिया है, बल्कि रोजगार भी पैदा किया है और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है।

● **अनुकूल कृषि पद्धतियाँ:**

- जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने से खाद्य सुरक्षा बेहतर हुई है और सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार हुआ है।

चुनौतियाँ और मुद्दे

● **डेटा और निगरानी:**

- जलवायु-उत्तरदायी बजटिंग के लिए डेटा संग्रह और निगरानी की सटीकता सर्वोपरि है।
 - भारत को सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए अपनी डेटा अवसंरचना को मजबूत करने की जरूरत है।

● **राजकोषीय बाधाएँ:**

- जलवायु परिवर्तन से निपटने से वित्त पर दबाव पड़ता है। भारत को राजकोषीय बाधाओं से निपटने के लिए नवीन वित्तपोषण तंत्र का पता लगाना चाहिये तथा साझेदारी विकसित करनी चाहिये।

भारत के सार्वजनिक व्यय में जलवायु-उत्तरदायी बजट को एकीकृत करना राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों जिम्मेदारियों के अनुरूप है। यह दृष्टिकोण निवेश दक्षता को बढ़ा सकता है, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर कर सकता है और संयुक्त राष्ट्र और UNFCCC समझौतों के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकता है। जलवायु-उत्तरदायी बजट ढाँचे की दिशा में भारत के प्रयास सतत विकास और हरित, अधिक लचीले भविष्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

2. **अत्यधिक एवं अविवेकपूर्ण रेत खनन की पारिस्थितिक लागत इसके आर्थिक लाभों से कहीं अधिक है। धारणीय रेत खनन के महत्त्व के संदर्भ में चर्चा कीजिये।** (150 शब्द) 10

The ecological cost of excessive and indiscriminate sand mining far outweighs its economic benefits. Discuss in the context of the importance of sustainable sand mining. (150 Words) 10

उत्तर: रेत खनन एक आकर्षक उद्योग है जिसने निर्माण, विनिर्माण और औद्योगिक प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका के कारण हाल के दशकों में अत्यधिक वृद्धि देखी है। हालाँकि, यह आर्थिक वरदान एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक लागत पर प्राप्त होता है।

प्राकृतिक वासों का विनाश:

- अविवेकपूर्ण रेत खनन में अक्सर नदी तलों और तटीय क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में रेत निकालना शामिल होता है।
 - यह प्रक्रिया जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है और मछली, अकशेरुकी और अन्य जलीय जीवों के महत्वपूर्ण आवासों को नष्ट कर देती है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार, रेत खनन निवास स्थान के नुकसान का एक प्रमुख कारक है और इससे उन प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बन सकता है, जो इन पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर हैं।

जल गुणवत्ता पर प्रभाव:

- अत्यधिक रेत खनन से नदी और भूजल स्तर में बदलाव आ सकता है, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है और जिससे लवणता बढ़ जाती है।
- विश्व वन्यजीव कोष (WWF) के शोध से संकेत मिलता है कि रेत खनन मीठे पानी के स्रोतों में खारे पानी के प्रवेश को तीव्र करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ा सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और पेयजल आपूर्ति दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

कटाव और तटीय भेद्यता:

- The Journal of Coastal Research की रिपोर्ट के अनुसार, अनियमित रेत खनन समुद्र तट के क्षरण में योगदान देता है, जिससे तटीय आबादी की सुरक्षा और आजीविका खतरे में पड़ जाती है।

जैव विविधता पर प्रभाव:

- रेत खनन कछुओं और तटीय पक्षियों के घोंसले के स्थानों का विनाश करते हैं, जिससे इन प्रजातियों की संख्या में गिरावट आ सकती है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अत्यधिक रेत खनन से प्रवासी पक्षियों और समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थलों और खाद्य क्षेत्रों का नुकसान हो सकता है।

सामाजिक और आर्थिक परिणाम:

- हालाँकि, रेत खनन से अल्पकालिक आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन अक्सर इसके दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम होते हैं।
 - कटाव और आवास विनाश मत्स्य पालन और पर्यटन को नुकसान पहुँचाते हैं, जो की कई समुदायों के लिए आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG) पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के महत्व पर जोर देते हैं।

• धारणीय रेत खनन के महत्व:

- पर्यावरण संरक्षण: यह कटाव को कम कर, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करता है।
- बुनियादी अवसंरचना का विकास: निर्माण के लिये स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- जल संसाधनों का संरक्षण: भूजल पुनर्भरण को बनाए रखता है साथी पानी की गुणवत्ता को भी बनाए रखता है।
- सामाजिक कल्याण: आजीविका को संबल प्रदान करता है और साथ ही संघर्षों को कम करता है।

- सतत रेत खनन पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संसाधनों के दोहन को संतुलित करता है।

अंधाधुंध रेत खनन के गंभीर पारिस्थितिक परिणाम होते हैं, जिनमें पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान, जल की गुणवत्ता में गिरावट और जैव विविधता के खतरे शामिल हैं। हालाँकि उद्योग लाभदायक है, लेकिन इसके दीर्घकालिक नुकसान अल्पकालिक लाभ से अधिक हैं। इन नुकसानों को कम करने के लिए, पुनर्चक्रित रेत जैसे विकल्पों के बेहतर विनियमन और प्रचार के माध्यम से टिकाऊ रेत खनन प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिये।

3. क्या भारत को उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में दंगों और मानवाधिकारों के हनन की चिंताओं को ध्यान में रखकर, संघर्षपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए, कुछ क्षेत्रों में AFSPA के निरंतर प्रयोग पर पुनर्विचार करना चाहिए? परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Should India reconsider the continued application of AFSPA in certain regions, given concerns about riots in northeastern states and human rights abuses, while also addressing the security needs in conflict areas? Examine. (150 Words) 10

उत्तर: सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम (AFSPA) 1958, जिसे कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लागू किया गया था लेकिन यह भारत में, खासकर पूर्वोत्तर में मणिपुर जैसे उग्रवाद और अशांति वाले क्षेत्रों में बहस का विषय रहा है।

मणिपुर से संबंधित चिंताएँ:

- सुरक्षा अभियानों के दौरान कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन और नागरिक हताहतों की घटनाओं के कारण मणिपुर AFSPA बहस का केंद्र बिंदु रहा है।
 - 2004 में थंगजाम मनोरमा की न्यायेतर हत्या और उसके बाद कार्यकर्ता इरोम शर्मिला द्वारा विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल इन चिंताओं का प्रतीक हैं।
 - इन घटनाओं ने क्षेत्र में AFSPA जैसे कानून की जरूरत पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
 - मणिपुर में हालिया संघर्ष भी AFSPA पर सवाल उठाता है।

विशिष्ट क्षेत्रों में AFSPA का पुनर्मूल्यांकन

यह मुद्दा, कि क्या भारत को कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA), 1958 के लागू अनुप्रयोग का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिये, एक जटिल और महत्वपूर्ण मामला है। पूर्वोत्तर राज्यों में उपद्रवों, मानवाधिकारों के हनन और संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा जरूरतों को संबोधित करने की अनिवार्यता के बारे में चिंताओं को संतुलित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

AFSPA पर पुनर्विचार



समर्थन:

- **मानवाधिकार और कूटनीति:** अधिकारों के हनन और उपद्रवों के बारे में चिंताएँ AFSPA की समीक्षा की आवश्यकता पर जोर देती हैं। मानवाधिकारों का दुरुपयोग भारत की वैश्विक छवि और संबंधों को नुकसान पहुँचाती हैं।
- **सामुदायिक संबंध:** अत्यधिक शक्तियाँ स्थानीय लोगों को अलग-थलग कर देती हैं, जिससे संघर्ष वाले क्षेत्रों में विश्वास निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है।
- **सुरक्षा और अधिकारों को संतुलित करना:** पुनर्मूल्यांकन से सुरक्षा और अधिकारों के बीच संतुलन प्राप्त होता है।
- **वैकल्पिक दृष्टिकोण:** आधुनिक तरीके AFSPA के बिना सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, नुकसान को कम कर सकते हैं।
- **कानूनी ढाँचे में सुधार:** AFSPA को निरस्त/बदलने से बेहतर कानूनी मानदंड बन सकते हैं।

विरोध:

- **सुरक्षा प्राथमिकता:** संघर्षों से निपटने, व्यवस्था बनाए रखने के लिए AFSPA महत्वपूर्ण है।
- **उग्रवाद की रोकथाम:** यह उग्रवाद को रोकता है, त्वरित कार्रवाई में सहायता करता है।
- **कार्मिक सुरक्षा:** खतरनाक क्षेत्रों में कार्मिकों की रक्षा करता है।
- **राष्ट्रीय एकता:** संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में एकता कायम रखना।
- **परिचालन तीव्रता:** खतरों पर त्वरित प्रतिक्रिया की अनुमति देने के कारण।

संतुलित दृष्टिकोण:

- **क्षेत्रीय संदर्भ:** मामले-दर-मामले आधार पर AFSPA की प्रयोज्यता का आकलन करना, उन क्षेत्रों की पहचान करना, जहाँ सामान्य कानून प्रवर्तन तंत्र पर्याप्त हो सकते हैं।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा नैतिक और कानूनी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।
- **AFSPA से इतर रणनीतियाँ:** वैकल्पिक सुरक्षा रणनीतियों की खोज करना जो मानवाधिकारों का सम्मान करती हैं और संघर्ष स्थितियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करती हैं।

सिफारिशें और विचार:

- **जीवन रेड्डी समिति:**

- 2004 में, न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी के नेतृत्व में एक समिति का गठन पूर्वोत्तर राज्यों में AFSPA की समीक्षा के लिए किया गया था। समिति ने AFSPA को निरस्त करने और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश की।
- इसने अधिक मापित कानूनी ढाँचे के माध्यम से सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC):**

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट में भी AFSPA पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया गया। इसने एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का प्रस्ताव दिया, जहां अधिनियम केवल तभी लागू किया जाना चाहिये जब बिल्कुल आवश्यक हो तथा नियमित कानून प्रवर्तन तंत्र को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

- **विशेषज्ञ राय:** पूर्व गृह सचिव जी.के.पिल्लई ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए AFSPA को हटाने का समर्थन किया।

AFSPA का पुनर्मूल्यांकन एक संतुलित दृष्टिकोण की मांग करता है जो अधिकारों, सुरक्षा और संघर्षों के बारे में चिंताओं को संबोधित करता है। समितियों और विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि बेहतर रणनीति तैयार करने में सहायता कर सकती है।

4. भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के संदर्भ में चंद्रयान-3 मिशन के महत्त्व की चर्चा कीजिये। साथ ही, पृथ्वी से चंद्रमा तक की यात्रा के दौरान अंतरिक्षयान के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिये।

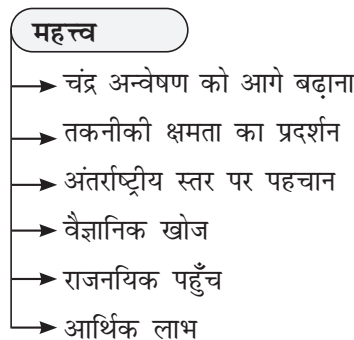
(150 शब्द) 10

Discuss the significance of the Chandrayaan-3 mission in the context of India's space achievements. Also, highlight the major challenges faced by the spacecraft during its journey from Earth to the Moon.

(150 Words) 10

उत्तर: भारत ने अपने चंद्रयान-3 मिशन को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर विश्व का पहला देश बना यह इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है। अपने पूर्ववर्तियों, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 की सफलताओं के आधार पर, यह मिशन चंद्रमा के रहस्यों, वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी कौशल के बारे में हमारी समझ को और विस्तारित करने के लिए तैयार है।

महत्त्व:



● **चंद्र अन्वेषण को आगे बढ़ाना:**

- मिशन चंद्रमा की खोज और अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार करने के लिए यह भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का दर्शाता है।
- यह पिछले चंद्रयान मिशनों की सफलता का अनुसरण करता है, जो चंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है।

● **तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन:**

- चंद्रयान-3 चंद्र मिशन के लिए जटिल अंतरिक्ष यान के डिजाइन, निर्माण और लॉन्च करने की क्षमता का प्रदर्शन करके भारत की तकनीकी शक्ति को रेखांकित करता है।
- मिशन में जटिल इंजीनियरिंग, नेविगेशन और संचार प्रणालियाँ शामिल हैं, जो इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति को उजागर करती हैं।
- इसके लैंडर प्रौद्योगिकी विकास और लैंडिंग प्रयास ने सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक में भारत की क्षमता को आगे बढ़ाया।

● **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान:**

- मिशन महत्वाकांक्षी और उन्नत अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत का कद बढ़ाता है।
- सफल निष्पादन से अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक विश्वसनीय और सक्षम भागीदार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।

● **वैज्ञानिक खोज:**

- मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह, संरचना और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करना है।
- ऐसी जानकारी चंद्रमा की उत्पत्ति, विकास और संभावित संसाधनों की वैश्विक समझ में योगदान देती है।

● **राजनयिक पहुँच:**

- यह अंतरिक्ष अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी के अवसर प्रदान करता है।
- यह अन्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के साथ राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देता है और वैज्ञानिक ज्ञान के वैश्विक आदान-प्रदान में योगदान देता है।

● **आर्थिक लाभ:**

- चंद्रयान-3 का सफल निष्पादन भारत के अंतरिक्ष उद्योग के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और कुशल रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।

पृथ्वी से चंद्रमा तक की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:

- चुनौतियाँ**
- सौर हवाएँ
 - पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कमी
 - उच्चतम तापमान
 - निर्वात की स्थिति
 - प्रक्षेपण के दौरान कंपन
 - संचार में विलंब
 - प्रवेश, अवतरण और लैंडिंग (EDL)
 - ऊर्जा प्रबंधन

- **सौर हवाएँ:**

- अंतरिक्ष यान सौर हवाओं के संपर्क में हैं जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नुकसान पहुँचा सकता है और यान के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को प्रभावित कर सकता है।

- **पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कमी:**

- अंतरिक्ष यान में बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सुरक्षा कवच का अभाव है। यह इसे सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण के पूर्ण प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे सिस्टम विफलताओं और आँकड़ों की हेरा-फेरी (Data Corruption) का खतरा बढ़ जाता है।

- **उच्चतम तापमान:**

- अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश से छाया की ओर बढ़ते समय अत्यधिक तापमान में उतार-चढ़ाव का अनुभव करता है। तापमान अंतर सामग्री के विस्तार और संकुचन का कारण बन सकता है, जिससे संभावित रूप से संरचनात्मक तनाव और घटक विफलता हो सकती है।

- **निर्वात की स्थिति:**

- कुछ सामग्री आउटगैसिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से वैक्यूम स्थितियों के कारण फँसे हुए वायु अणुओं को छोड़ सकती हैं, जो संवेदनशील सतहों पर जमा हो सकती हैं और समस्याएँ पैदा कर सकती हैं।

- **प्रक्षेपण के दौरान कंपन:**

- प्रक्षेपण के दौरान, अंतरिक्ष यान तीव्र कंपन, झटके और बल के अधीन होता है। ये कंपन संभावित रूप से घटकों को नुकसान पहुँचा सकते हैं या उखाड़ सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान की समग्र कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

- **संचार में विलंब:**

- पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की विशाल दूरी संचार विलंब का कारण बनती है, जिसे विलंबता कहा जाता है। वास्तविक समय पर नियंत्रण और डेटा ट्रांसमिशन चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए उन्नत योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है।

- **प्रवेश, अवतरण और लैंडिंग (EDL):**

- चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सटीक लैंडिंग प्राप्त करने में एक जटिल EDL चरण शामिल होता है। चंद्रमा के विरल वातावरण के माध्यम से अभ्यास करने और खतरों से बचते हुए सटीक लैंडिंग के लिए परिष्कृत नेविगेशन और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

- **ऊर्जा प्रबंधन:**

- अंतरिक्ष यान को अपनी विद्युत् आपूर्ति को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता है, खासकर ग्रहण की अवधि के दौरान जब यह चंद्रमा की छाया में जाता है। निरंतर संचालन के लिए पर्याप्त विद्युत् उत्पादन और भंडारण आवश्यक है।

चंद्रयान-3 ने चंद्रमा तक की अपनी यात्रा की चुनौतियों का रणनीतिक रूप से सामना किया है। यह प्रतिक्रिया के माध्यम से विकिरण प्रतिकूल इलेक्ट्रॉनिक, सहनशाली सामग्री तथा उन्नत नेविगेशन का उपयोग करके विकिरण प्रभावों को कम करता है। और सटीक प्रवेश और लैंडिंग सुनिश्चित करता है। कार्यक्षमता की सुरक्षा के लिए कुशल विद्युत् प्रबंधन, उपकरण सुरक्षा और अनुकूलित संचार प्रोटोकॉल नियोजित किए जाते हैं। ये उपाय नवाचार और वैज्ञानिक उन्नति के प्रति इसरो की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को मजबूत करते हैं और चंद्र घटनाओं की हमारी समझ में योगदान करते हैं।

5. किसानों को बाजार के शोषण से बचाने और स्थिर आय सुनिश्चित करने में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के महत्त्व को समझाइये। विभिन्न फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द) 10

Explain the significance of Minimum Support Prices (MSP) in protecting farmers from market exploitation and ensuring a stable income. Evaluate the challenges in implementing MSP across diverse crops. (150 Words) 10

उत्तर: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कृषि फसलों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बेंचमार्क मूल्य है। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम गारंटीकृत आय प्राप्त हो। वर्तमान में, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश करता है।

MSP का महत्त्व:

MSP का महत्त्व

- आय सुरक्षा
- समर्थन मूल्य
- कृषि उत्पादकता
- समाज कल्याण
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार
- कृषि सुधारों के लिए नीतिगत साधन

● आय सुरक्षा:

- MSP किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य (आधार मूल्य) सुनिश्चित करके आय सुरक्षा प्रदान करता है और किसानों को बाजार की कीमतों की अस्थिरता से बचाता है, खासकर अधिशेष उत्पादन या मूल्य गिरावट के समय।
- आय में यह स्थिरता किसानों के सामने आने वाले आर्थिक संकट को कम करने में मदद करती है।
- 2021-22 रबी सीजन में सरकार ने MSP पर 146.4 मिलियन टन गेहूँ और चावल की खरीद की, जो कुल खरीद लक्ष्य का 86% था। यह एक सीजन में MSP पर गेहूँ और चावल की अब तक की सबसे अधिक खरीद थी। सरकार ने किसानों को MSP के रूप में कुल 1.95 लाख करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।

● समर्थन मूल्य:

- सरकार MSP पर खरीद करती है, मूल्य स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक बनाए रखती है।
- किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाता है और उचित रिटर्न सुनिश्चित करता है।
- 2020-21 में MSP पर रिकॉर्ड 43.36 मिलियन टन गेहूँ की खरीद हुई।

● कृषि उत्पादकता:

- MSP निवेश, आधुनिक प्रथाओं और उच्च उत्पादकता को प्रोत्साहित करता है।
- खाद्य उत्पादन बढ़ाता है, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में योगदान देता है।
- MSP द्वारा समर्थित उच्च उपज वाली गेहूँ और चावल की किस्मों की शुरुआत से अधिक पैदावार हुई।

● समाज कल्याण:

- MSP आवश्यक वस्तुओं के लिए स्थिर कीमतें सुनिश्चित करता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समर्थन करता है।
- कमजोर वर्गों के लिए किफायती खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बनाए रखना।

● **ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार:**

- MSP कृषि आय का समर्थन करता है, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देता है।
- ग्रामीण आजीविका में सहायता करता है, आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करता है, प्रवासन पर अंकुश लगाता है।

● **कृषि सुधारों के लिए नीतिगत साधन:**

- फसल उत्पादन, विविधीकरण और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।
- कृषि क्षेत्र में चर्चा और सुधारों को बढ़ावा देता है, बाजार-उन्मुख समाधानों को बढ़ावा देता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

MSP कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियाँ:

चुनौतियाँ

- कवरेज और पहुँच
- बाजार की विकृतियाँ और फसल असंतुलन
- खरीद और भंडारण अवसंरचना
- मूल्य असमानताएं और बिचौलियों द्वारा शोषण
- उत्पादन लागत और इनपुट सब्सिडी
- सरकार पर वित्तीय बोझ

● **कवरेज और पहुँच:**

- MSP संचालन चुनिंदा फसलों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को छोड़ देता है।
- 2020-21 में गेहूँ और चावल की सीमित खरीद (क्रमशः 22% और 20%) सीमित कवरेज को दर्शाती है।

● **बाजार की विकृतियाँ और फसल असंतुलन:**

- गेहूँ और चावल जैसी विशिष्ट फसलों पर भारी निर्भरता फसल प्रतिरूप को बाधित करती है।
- मूल्य असमानताओं के परिणामस्वरूप पसंदीदा फसलों का अधिक उत्पादन होता है और विविधीकरण सीमित होता है।
- उदाहरण के लिए, 2022-23 में गेहूँ की औसत कीमत ₹2,015 प्रति क्विंटल, जबकि दालों की औसत कीमत ₹6,100 प्रति क्विंटल। इसका अर्थ यह है कि किसान गेहूँ की जगह दालें उगाकर तीन गुना ज्यादा कमाई कर सकते थे।

● **खरीद और भंडारण अवसंरचना:**

- अपर्याप्त खरीद और भंडारण सुविधाओं के कारण फसल के बाद नुकसान होता है और खराब गुणवत्ता वाला रख-रखाव होता है।
- 2022-23 में, MSP पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए गेहूँ का केवल 75% ही खरीदा गया था, जो भंडारण चुनौतियों का संकेत देता है।

● **मूल्य असमानताएं और बिचौलियों द्वारा शोषण:**

- MSP के बावजूद, बिचौलियों के प्रभुत्व के कारण मूल्य असमानताएँ बनी रहती हैं।
- बिचौलियों की चालाकी से किसानों की कमाई कम होती है।
- 2022-23 में, बिचौलियों के प्रभाव के कारण गेहूँ की फार्म गेट कीमतें MSP से कम थीं।

● **उत्पादन लागत और इनपुट सब्सिडी:**

- MSP बढ़ती इनपुट लागत को कवर नहीं कर सकता है, जिससे किसान की लाभप्रदता प्रभावित होगी।
- जब MSP उत्पादन लागत से कम हो जाता है तो कम लाभप्रदता और वित्तीय तनाव उत्पन्न होता है।

○ 2022-23 में, सरकारी इनपुट सब्सिडी गेहूँ की वास्तविक उत्पादन लागत का केवल 75% कवर करती थी।

● **सरकार पर वित्तीय बोझ:**

○ MSP पर खरीद और बफर स्टॉक बनाए रखने से सरकारी वित्त पर बोझ पड़ता है।

○ अधिशेष उत्पादन और वैश्विक मूल्य में गिरावट के दौरान MSP के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

○ 2022-23 में सरकार द्वारा खाद्यान्न खरीद और भंडारण पर 2.0 ट्रिलियन रूपये खर्च किया गया।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें डेटा-संचालित नीति निर्माण, क्षेत्र-विशिष्ट MSP निर्धारण, कुशल खरीद तंत्र और बाजार-उन्मुख सुधार शामिल हों। MSP का सफल कार्यान्वयन किसानों, उपभोक्ताओं और समग्र कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरतों को संतुलित करने पर निर्भर करता है।

6. निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके लिए क्या अर्थ है?

What does each of the following quotations mean to you?

(a) “हमें भाइयों की तरह एक साथ रहना सीखना चाहिए या मूर्खों की तरह एक साथ नष्ट हो जाना चाहिए।”
- मार्टिन लूथर किंग जूनियर (150 शब्द) 10

“We must learn to live together as brothers or perish together as fools.” – Martin Luther King Jr. (150 Words) 10

उत्तर: “हमें भाइयों की तरह एक साथ रहना सीखना चाहिये या मूर्खों के रूप में एक साथ नष्ट हो जाना चाहिये” एकता और सहयोग के महत्त्व के बारे में यह एक शक्तिशाली कथन है। यह सुझाव देता है कि यदि हम शांति और सद्भाव से एक साथ रहना नहीं सीखते हैं, तो हम सभी को इसके परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि-

- **मानवता की परस्पर निर्भरता:** मार्टिन लूथर का यह कथन मानवता के सामने आने वाले महत्वपूर्ण विकल्प पर प्रकाश डालता है: सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को अपनाना या कलह और अज्ञानता के कारण सामूहिक पतन का सामना करना।
- **एकता के रूप में भाईचारा:** “भाइयों के रूप में एक साथ रहने” की उपमा एकता, सहानुभूति और साझा मूल्यों की आवश्यकता पर बल देती है, जो मतभेदों से परे पारिवारिक बंधन के समान है।
- **विभाजन पर सामंजस्य:** मार्टिन लूथर का संदेश नस्लीय, सांस्कृतिक और वैचारिक विभाजनों को पार करने के आव्हान के साथ प्रतिध्वनित होता है, यह स्वीकार करते हुए कि हमारा अस्तित्व हमारी साझा मानवता को पहचानने पर निर्भर है।
- **विभाजन के खतरे:** “मूर्खों के रूप में एक साथ नष्ट हो जाना” कथन विभाजन के परिणामों और हमारे अंतर्संबंध को समझने में विफलता के खिलाफ चेतावनी देता है तथा संघर्ष पर सहयोग को चुनने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।
- **वैश्विक प्रासंगिकता:** संघर्षों और ध्रुवीकरण से जूझ रही दुनिया में, मार्टिन लूथर के शब्द विविधता को अपनाने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए संवाद को बढ़ावा देने के महत्त्व को रेखांकित करते हैं।

वैश्वीकृत दुनिया में, मार्टिन लूथर के शब्द हमें सौहार्दपूर्ण ढंग से सह-अस्तित्व रखने और एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने की याद दिलाते हैं। भविष्य के निर्माण के लिए हमें अज्ञानता और असहिष्णुता से ऊपर उठना होगा जहां भाईचारे के धागे आपसी समृद्धि का ताना-बाना बुनते हैं और जैसा कि साइमन मेनवारिंग (Simon Mainwaring) ने भी कहा है कि “यह या तो सहयोग और समृद्धि है या विखंडन और विफलता है।”

(b) “चरित्र एक पेड़ की तरह है और प्रतिष्ठा एक छाया की तरह है। छाया वही है जिसके बारे में हम सोचते हैं; पेड़ ही वास्तविक चीज है।” –अब्राहम लिंकन (150 शब्द) 10

“Character is like a tree and reputation is like a shadow. The shadow is what we think of it; the tree is the real thing.” - Abraham Lincoln (150 words) 10

उत्तर: उपर्युक्त कथन का अर्थ है कि हमारी प्रतिष्ठा वह है जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा चरित्र वह है जो हम वास्तव में हैं। जैसे-पेड़ एक मजबूत चीज है, जबकि छाया किसी और चीज का प्रतिबिंब मात्र है।

कथन का अन्य आशय:

- **चरित्र एक नींव के रूप:** लिंकन की सादृश्यता एक मजबूत पेड़ और एक व्यक्ति के चरित्र के बीच एक समानता दर्शाती है, जो कार्यों को सूचित करने वाले अपरिवर्तनीय मूल के रूप में चरित्र की भूमिका पर प्रकाश डालती है।
- **सत्यनिष्ठा एवं मूल्य:** एक पेड़ की जड़ों की तरह चरित्र का पोषण लगातार नैतिक विकल्पों द्वारा किया जाता है, जो बाहरी प्रभावों की परवाह किए बिना किसी के मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाता है।
- **प्रतिष्ठा की क्षणिक प्रकृति:** प्रतिष्ठा से छाया की तुलना क्षणभंगुर प्रकृति को रेखांकित करती है, जिसे बाहरी धारणाओं और परिस्थितियों द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है, जो अक्सर क्षणिक और निंदनीय होती है।
- **धारणा से अधिक प्रामाणिकता:** लिंकन की बुद्धि प्रामाणिकता और नैतिक दृढ़ता पर बल देते हुए, प्रतिष्ठा के प्रति जुनूनी होने के बजाय एक ठोस चरित्र के निर्माण को प्राथमिकता देने की सलाह देती है।
- **मार्गदर्शक नैतिक दिशा-निर्देश:** सोशल मीडिया और त्वरित राय की दुनिया में, लिंकन का उद्धरण एक नैतिक दिशासूचक के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तियों से प्रतिष्ठा की बदलती छाया के बावजूद अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने का आग्रह करती है।
- **स्थायी सीख:** उद्धरण का कालातीत पाठ एक अनुस्मारक के रूप में प्रतिध्वनित होता है कि हालाँकि प्रतिष्ठा डगमगा सकती है, किसी का चरित्र ही सत्यनिष्ठा और सदाचार का सच्चा माप है।

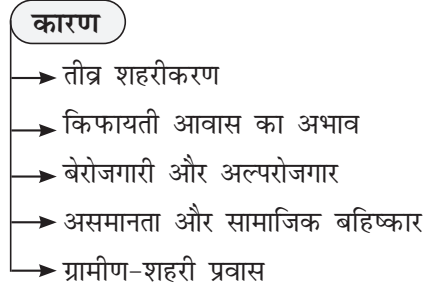
अस्थिर जनमत के समय में, लिंकन के शब्द हमें धारणा से अधिक चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाते हैं। एक मजबूत पेड़ की तरह, हमारा चरित्र अटल खड़ा है, प्रामाणिकता और नैतिक दृढ़ता का प्रमाण है, तब भी जब हमारे आस-पास की दुनिया बदल जाती है जैसा कि राल्फ वाल्डो एमर्सन ने भी कहा है, “चरित्र बुद्धि से ऊँचा है।”

7. शहरी निर्धनता को परिभाषित करते हुए इसके अंतर्निहित कारणों को स्पष्ट कीजिये। शहरी निर्धनता का सामना करने वाले लोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा इसके उन्मूलन हेतु पहलों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Define urban poverty and elucidate its underlying causes. Analyze the challenges faced by the people facing urban poverty and discuss the initiatives to eradicate it. (250 words) 15\

उत्तर: शहरी गरीबी एक शहरी क्षेत्र में भोजन, आश्रय, वस्त्र, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कमी की स्थिति है। यह उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें शहरी क्षेत्रों के भीतर व्यक्ति या समुदाय अपर्याप्त जीवन स्तर, बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच और निम्न आय स्तर का अनुभव करते हैं, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है।

शहरी गरीबी के अंतर्निहित कारण:



● तीव्र शहरीकरण:

- बेहतर आर्थिक संभावनाओं की तलाश में लोगों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन से शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि होती है, जो शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास की गति को पार कर जाती है।
 - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत में शहरी आबादी 2050 तक 814 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।

● किफायती आवास का अभाव:

- **अपर्याप्त आपूर्ति:** आवास की बढ़ती मांग आपूर्ति से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च किराया लागत और भीड़-भाड़ होती है।
 - मुंबई, दिल्ली और जैसे शहरों में, शहरी निवासियों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत (30%) झुगियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहता है।

● बेरोजगारी और अल्परोजगार:

- **संरचनात्मक मुद्दे:** रोजगार सृजन की कमी, कौशल अंतराल और औपचारिक श्रम बाजारों तक सीमित पहुँच उच्च बेरोजगारी दर में योगदान करती है।
 - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि दुनिया के सभी श्रमिकों में से लगभग 61% अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं, जिसमें अक्सर नौकरी की सुरक्षा और लाभों का अभाव होता है।

● असमानता और सामाजिक बहिष्कार:

- **भेदभाव:** अल्पसंख्यकों और प्रवासियों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच में बाधा उत्पन्न करते हैं।
 - विश्व बैंक के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में आय असमानता अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है।

● ग्रामीण-शहरी प्रवास:

- शहरी गरीब मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबों का अतिप्रवाह है जो वैकल्पिक रोजगार और आजीविका की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।
 - ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कमी (पुश फैक्टर), शहरी क्षेत्रों में तेजी से औद्योगीकरण (पुल फैक्टर) के कारण असममित विकास के कारण पलायन हो रहा है।
- अपर्याप्त शिक्षा और कौशल, कम वेतन वाली नौकरियाँ, ऋणग्रस्तता, मुद्रास्फीति, प्राकृतिक आपदाएँ आदि कुछ अन्य कारक हैं, जिन्होंने शहरी गरीबी के बढ़ने में भी योगदान दिया।

शहरी निर्धनों के समक्ष चुनौतियाँ:

● बुनियादी सेवाओं तक अपर्याप्त पहुँच:

- शहरी निर्धन अक्सर भीड़-भाड़ वाली परिस्थितियों में रहते हैं। इनके पास अक्सर साफ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का भी अभाव होता है जिससे स्वास्थ्य और कल्याण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

● **शिक्षा संबंधी असमानताएँ:**

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** शहरी गरीब अक्सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक गतिशीलता और गरीबी के चक्र को तोड़ने के अवसर सीमित हो जाते हैं।
 - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा शहरी भारत में शिक्षा की स्थिति के अनुसार प्राथमिक (8%) की तुलना में उच्च प्राथमिक (15%) में ड्रॉपआउट दर अधिक है।

● **खाद्य असुरक्षा:**

- **उच्च खाद्य कीमतें:** बढ़ती खाद्य कीमतों और किफायती बाजारों तक सीमित पहुँच के कारण शहरी गरीब समुदायों को पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
 - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय का अनुमान है कि भारत में लगभग 23.9% शहरी परिवारों ने खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया है।

शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार के कार्यक्रम:

शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार के कार्यक्रम

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT)
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- स्वच्छ भारत अभियान
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)
- जल जीवन मिशन (शहरी)

● **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM):**

- इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को अपना व्यवसाय शुरू करने या नौकरी प्राप्त करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

● **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):**

- इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इसके दो घटक हैं: PMAY-ग्रामीण और PMAY-शहरी। PMAY-शहरी योजना पात्र लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

● **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM):**

- इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजारों तक पहुँच प्रदान करके उनके जीवन में सुधार करना है।

● **कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT):**

- इस योजना का लक्ष्य भारत के 500 शहरों के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है। इसमें जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क और सार्वजनिक परिवहन की परियोजनाएँ शामिल हैं।

● **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):**

- इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। यह आईटी, विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

● **स्वच्छ भारत अभियान:**

- इस अभियान का लक्ष्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। इससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार करने और बीमारियों की घटनाओं को कम करने में मदद मिलती है।

● **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):**

- यह योजना शहरी गरीबों को छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

● **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM):**

- इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करके उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है।

● **जल जीवन मिशन (शहरी):**

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत सभी वैधानिक कस्बों में कार्यात्मक नल के माध्यम से सभी घरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने की घोषणा की गई है।

शहरी गरीबी को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर विचार करता है तथा इसमें सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग शामिल होता है।

8. जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय आपदा न बनने देना भारत के पक्ष में होगा। विश्लेषण कीजिये।

(250 शब्द) 15

It will be in India's favour to not let the demographic dividend become a demographic disaster.

Analyse.

(250 words) 15

उत्तर: भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश उस संभावित आर्थिक लाभ को संदर्भित करता है जो एक देश युवा और बढ़ती आबादी से प्राप्त कर सकता है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भारत सबसे युवा है, यहाँ की औसत आयु 29 वर्ष है। हालाँकि, भारत के लिए इस जनसांख्यिकीय लाभांश को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है ताकि इसे जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने से रोका जा सके।

ऐसी स्थिति को टालना भारत के पक्ष में क्यों:

● **आर्थिक विकास:**

- बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी के साथ, भारत में उत्पादकता बढ़ाने, आर्थिक विकास को गति देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है।
- शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन में निवेश करके, भारत अपनी युवा आबादी का लाभ उठा सकता है और एक मजबूत कार्यबल तैयार कर सकता है जो देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकता है।

● **मानव विकास:**

- यह सुनिश्चित करना कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इससे उनका समग्र विकास होगा।
- मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करके, भारत जीवन स्तर में सुधार, गरीबी को कम करने और साक्षरता और जीवन प्रत्याशा जैसे सामाजिक संकेतकों को बढ़ाने के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है।

● **सामाजिक स्थिरता:**

- उच्च युवा बेरोजगारी और मानव पूंजी का कम उपयोग सामाजिक अशांति और अस्थिरता को जन्म दे सकता है।
- युवाओं की रोजगार आवश्यकताओं को संबोधित करके और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर, भारत सामाजिक एकता बनाए रख सकता है तथा निराशा और असमानता से उत्पन्न होने वाले संभावित संघर्षों को रोक सकता है।

● **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:**

- तीव्र गति से आपस में जुड़ी दुनिया में, सुशिक्षित, कुशल और उत्पादक कार्यबल वाले देश वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।
- अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, भारत अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर सकता है तथा नवाचार एवं तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे सकता है।

हालाँकि, यदि भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रबंधन करने में विफल रहता है, तो इसके परिणामस्वरूप जनसांख्यिकीय आपदा हो सकती है:

● **बेरोजगारी और निर्धनता:**

- अपर्याप्त रोजगार सृजन और कौशल तथा बाजार की मांग के बीच बे-मेल उच्च युवा बेरोजगारी और व्यापक गरीबी का कारण बन सकता है।
- यह स्थिति सामाजिक कल्याण प्रणालियों पर दबाव डाल सकती है, आय असमानताओं को बढ़ा सकती है तथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

● **सामाजिक अशांति:**

- निराशा और बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी आबादी सामाजिक अशांति, विरोध प्रदर्शन और यहाँ तक कि राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है।
- इससे भारत के विकास में बाधा आ सकती है और निवेश एवं विकास के लिए प्रतिकूल माहौल बन सकता है।

● **संसाधनों पर दबाव:**

- तेजी से बढ़ती जनसंख्या भोजन, पानी, आवास और स्वास्थ्य देखभाल जैसे संसाधनों की उपलब्धता पर दबाव डालती है।
- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और बुनियादी सेवाओं से जीवन की समग्र गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है और सतत विकास में बाधा आ सकती है।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को सफल बनाने के लिए सरकार और हितधारकों को शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन में निवेश करना चाहिये। इसमें ऐसी नीतियाँ शामिल हैं जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को संबोधित करते हुए उद्यमिता, नवाचार और समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं।

9. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी एवं मत्स्य पालन से संबंधित सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है? इस संदर्भ में डिजिटलीकरण के संभावित लाभों और चुनौतियों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

How can technology and digital platforms be leveraged to strengthen the functioning of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) dairy and fisheries cooperative societies? Discuss the potential benefits and challenges of digitalization in this context. (250 words) 15

उत्तर: जैसे-जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ भी अपने परिचालन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के विकल्प तलाश रही हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में ₹2516 करोड़ की राशि की घोषणा की गई थी।

डिजिटलीकरण के लाभ

डिजिटलीकरण के लाभ

- बेहतर वित्तीय पहुँच
- सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखना
- बाजार पहुँच को सुगम बनाना
- परिशुद्ध/सटीक कृषि
- वित्तीय समावेशन

बेहतर वित्तीय पहुँच:

- डिजिटल प्लेटफॉर्मों का एकीकरण PACS सदस्यों के लिए ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को महत्वपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कर सकता है।
 - यह तकनीकी संचार किसानों और मछुआरों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए सशक्त बनाता है।

सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखना:

- डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रुटिहीन रिकॉर्ड-कीपिंग और डेटा प्रबंधन के लिए मजबूत समाधान प्रदान करते हैं, जिससे त्रुटियों और धोखाधड़ी गतिविधियों की संभावना कम हो जाती है।
 - यह अंतर्निहित पारदर्शिता और जवाबदेही इन सहकारी समितियों के कामकाज को समृद्ध करती है।

बाजार पहुँच को सुगम बनाना:

- प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में, बड़े बाजारों के लिए एक पुल के रूप में कार्य करती है।
 - वर्तमान समय की कीमत की जानकारी, एक विस्तारित ग्राहक आधार और उपज के लिए बेहतर सौदेबाजी की शक्ति सभी की पहुँच के भीतर है।

परिशुद्ध/सटीक कृषि:

- डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में, IoT सेंसर और ड्रोन जैसे डिजिटल उपकरण परिशुद्ध/सटीक कृषि की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
 - ये प्रौद्योगिकियाँ संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करती हैं, जिससे संभावित रूप से पैदावार और लाभप्रदता में वृद्धि होती है।
 - 2023 का आर्थिक सर्वेक्षण कृषि और संबद्ध गतिविधियों में प्रौद्योगिकी एकीकरण पर बल देता है।
 - यह सहकारी समितियों पर लक्षित सब्सिडी और कर प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल उपकरणों को अपनाने को प्रोत्साहित करने की वकालत करता है।

वित्तीय समावेशन:

- डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अपनाने से ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे उन्हें बचत करने, निवेश करने और ऋण तक पहुँचने की सुविधा प्राप्त होती है।

डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ

डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ

- डिजिटल डिवाइड
- साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ
- कौशल में अंतर
- लागत निहितार्थ

डिजिटल डिवाइड:

- ग्रामीण क्षेत्रों में अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढाँचे का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है।
 - डिजिटल प्लेटफॉर्म की निर्बाध उपलब्धता के लिए इस विभेद को समाप्त करना आवश्यक है।
 - नीति आयोग की रिपोर्ट कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
- **सिफारिशें:** डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने और डिजिटल सेवाओं की सुविधा के लिए ग्रामीण इलाकों में सामान्य सेवा केंद्रों की स्थापना पर केंद्रित हैं।

साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

- जैसे-जैसे सहकारी समितियाँ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ती हैं, वे साइबर खतरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं।
 - संवेदनशील वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय सर्वोपरि हैं।

कौशल में अंतर:

- कई PACS और सहकारी सदस्यों में इन प्लेटफार्मों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए डिजिटल साक्षरता की कमी हो सकती है।
 - इसके लिए व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण पहल आवश्यक हैं।

लागत निहितार्थ:

- मुख्यतया छोटी सहकारी समितियों के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे की खरीद और रख-रखाव वित्तीय रूप से कठिन हो सकता है।
 - प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकारी समर्थन अत्यावश्यक है।

PACS, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों के संचालन में प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों के एकीकरण से ग्रामीण कृषि और मत्स्यकी में क्रांति लाने की क्षमता है। हालाँकि, डिजिटल विभाजन और साइबर सुरक्षा जोखिम जैसी उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके, हम एक डिजिटल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जिससे कृषि और मत्स्य पालन दोनों को लाभ होगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

10. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Foreign Direct Investment (FDI) can act as an important source of non-debt finance for India's economic development. Discuss in the context of steps taken to boost FDI in India. (250 words) 15

उत्तर: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पूंजी और प्रौद्योगिकी लाकर तथा अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार में एकीकृत करके भारत के आर्थिक विकास को संचालित करता है। FDI को बढ़ावा देने की नीतियों ने इसे भारत के विकास के लिए गैर-ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश में कुल FDI प्रवाह \$70.97 बिलियन है।

उदारीकृत FDI नीतियाँ:

- भारत ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी FDI नीतियों को उदार बनाने हेतु लगातार काम किया है।
 - हाल के वर्षों में, इसने रक्षा, बीमा और एकल-ब्रांड खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 100% FDI की अनुमति दी है।
 - विश्व निवेश रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, भारत FDI के दुनिया के शीर्ष 10 प्राप्तकर्ताओं में से एक था, जिसने 2019 में +51 बिलियन का निवेश प्राप्त किया, जो 2018 में \$42 बिलियन से अधिक था। यह नीति उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।
 - विश्व निवेश रिपोर्ट, 2023 के संस्करण में कहा गया है कि भारत में कुल FDI 10 प्रतिशत बढ़कर 2021 में 44.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में प्रभावशाली 49.3 बिलियन डॉलर हो गया।

मेक इन इंडिया पहल:

- 2014 में शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना था।
 - इस पहल ने नियमों को सरल बनाकर और व्यापार करने में आसानी में सुधार करके FDI को प्रोत्साहित किया है।
 - परिणामस्वरूप, भारत ने देश में विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए एप्पल और सैमसंग जैसी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया।

डिजिटल इंडिया और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और संपन्न स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र ने प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स में FDI को आकर्षित किया है।
 - इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के स्टार्ट-अप सेक्टर में महत्वपूर्ण FDI प्रवाह देखा गया, जो 2020 में 9.3 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।

बुनियादी ढाँचे का विकास:

- राजमार्गों, बंदरगाहों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश, FDI को आकर्षित करने के लिए एक लक्षित क्षेत्र रहा है।
 - पाँच वर्षों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश लक्ष्य के साथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) ने विदेशी निवेशकों के लिए इन परियोजनाओं में भाग लेने के दरवाजे खोल दिए हैं।

कर सुधार:

- भारत ने कर सुधार किए हैं, जिसमें कॉर्पोरेट कर की दर को 22% तक कम करना शामिल है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है।
 - ये सुधार FDI गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाते हैं।
 - The Ernst & Young Attractiveness Survey India, 2020 के अनुसार 63% निवेशकों ने भारत के कर माहौल को अनुकूल पाया।

भारत की नीतिगत पहलों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से महत्वपूर्ण गैर-ऋण वित्त को आकर्षित किया है, जो आर्थिक विकास, नवाचार, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, भारत को FDI-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिये।

11. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिये तथा अर्थव्यवस्था में कोर मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए व्यवहार्य रणनीतियों की अनुशंसा कीजिये। (250 शब्द) 15

Highlight the differences between the Wholesale Price Index (WPI) and Consumer Price Index (CPI) and recommend viable strategies for managing core inflation in the economy. (250 words) 15

उत्तर:

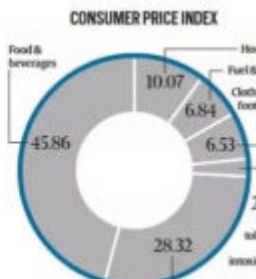
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दो प्रमुख संकेतक हैं जिनका उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन वे अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

थोक मूल्य सूचकांक एक संकेतक है जो थोक बाजार में थोक में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत में औसत परिवर्तन निर्धारित करता है। यह सूचकांक खुदरा विक्रेता तक पहुँचने से पहले विभिन्न चरणों में कमोडिटी की कीमतों में बदलाव की गणना करने में उपयोगी है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बदलाव का माप है, जो खुदरा में सीधे उपभोक्ता को बेची जाती हैं। इसे उस कीमत के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसे उपभोक्ता को एक निश्चित अवधि में वस्तुएँ या सेवाएँ खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है।

मुख्य अंतर:

- **दायरा और उद्देश्य:**
 - **थोक मूल्य सूचकांक:**
 - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है,
 - उत्पादन पक्ष पर केंद्रित
 - **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:**
 - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित,
 - उपभोक्ता-स्तर की कीमतों की पहचान करता है।
- **सेवा मूल्य:** WPI में सेवाएँ शामिल नहीं हैं, जबकि WPI उन्हें अपनी गणना में शामिल करता है।
- **वस्तुओं को महत्व:** WPI विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, जबकि CPI खाद्य पदार्थों पर अधिक जोर देता है।
- **समय संदर्भ:** WPI वित्तीय वर्ष को संदर्भ के रूप में उपयोग करता है, जबकि CPI कैलेंडर वर्ष पर आधारित है।
- **लेनदेन चरण:** WPI प्रारंभिक लेनदेन चरण को ट्रैक करता है, जबकि CPI अंतिम लेनदेन चरण को दर्शाता है।



	WPI	CPI
Released By	Office of Economic Advisor (Ministry of Commerce & Industry)	National Statistics Office (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Measures	Goods only	Both Goods & Services
Items covered	697	448(Rural Basket) 460 (Urban Basket)
Base year	2011-12	2012

CPI और WPI के बीच समानताएं:

- दोनों मुद्रास्फीति दर की गणना करते हैं।
- मौद्रिक नीति उपायों के रूप में WPI और CPI का उपयोग करके मूल्य स्थिरता के लिए प्रयास करती है।

मुद्रास्फीति से निपटने के उपाय

मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को संबोधित करने के लिए सरकारें और केंद्रीय बैंक कई तरह की रणनीतियाँ अपनाते हैं। इनमें से कुछ उपायों में शामिल हैं:

- **मौद्रिक नीति:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जैसे केंद्रीय बैंक, मुद्रास्फीति को बैंड (4% +/- 2% की लक्ष्य सीमा) के भीतर विनियमित करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करते हैं। रेपो दर और बैंक दर जैसी प्रमुख दरों को समायोजित करके वे अर्थव्यवस्था में उधार लेने की लागत और तरलता को प्रभावित करते हैं।
- **राजकोषीय नीति:** सरकारें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय अपनाती हैं। वे अत्यधिक व्यय को कम करने के लिए निजी व्यवसायों पर कर बढ़ा सकती हैं या मांग के दबाव को रोकने के लिए सरकारी व्यय में कटौती कर सकती हैं।
- **मूल्य नियंत्रण:** हालाँकि मूल्य नियंत्रण मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोक सकता है, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। कई प्रमाण बताते हैं कि सिर्फ मूल्य नियंत्रण लंबे समय तक मुद्रास्फीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं कर सकता है।

कोर मुद्रास्फीति से निपटने हेतु दृष्टिकोण:

- **मौद्रिक नीति उपाय :**
 - भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक लक्ष्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। महामारी के दौरान, इसने ऋण लेने और व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों को कम करके आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी।
- **आपूर्ति-पक्ष संवर्द्धन:**
 - भारत सरकार मुख्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति बाधाओं को समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, NAFED जैसे संगठनों के पास अपने दालों के स्टॉक का एक हिस्सा खुले बाजार में जारी करने से कीमतें स्थिर हो सकती हैं।
- **आर्थिक पुनरुद्धार के लिए नीतिगत उपाय:**
 - मुख्य मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए उपभोक्ता व्यय और निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सरकार उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने और उत्पादक क्षमताओं को पुनर्जीवित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन शुरू कर सकती है।
- **आय का पुनर्वितरण:**
 - प्रभावी नीतियों के माध्यम से आय असमानता को कम करने से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- **राजकोषीय विवेक:**
 - उत्तरदायी राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करना आवश्यक है। फिजूलखर्ची में कटौती करना, संपत्ति की बिक्री और नीलामी जैसे नए राजस्व स्रोतों की खोज करना तथा निवेशकों का विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण घटक हैं।

एक गतिशील आर्थिक माहौल में, अर्थव्यवस्था की विशिष्ट चुनौतियों तथा अवसरों पर विचार करते हुए इन उपायों को अपनाने और संयोजित करने से मुख्य मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है। इन रणनीतियों को विवेकपूर्ण तरीके से नियोजित करके, अर्थव्यवस्थाएं स्थिर मूल्य स्तर बनाए रख सकती हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं और नागरिकों की भलाई सुनिश्चित कर सकती हैं।

12. शासन में शुचिता के महत्त्व तथा लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिये। अपने उत्तर को, देश में हाल के प्रशासनिक और राजनीतिक विकास से संबंधित उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the significance of probity in governance and its role in ensuring transparency, accountability and ethical conduct in public administration. Illustrate your answer with relevant examples from recent administrative and political developments in the country. (250 words) 15

उत्तर:

शासन में शुचिता का तात्पर्य सार्वजनिक मामलों के संचालन में नैतिक सिद्धांतों, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के पालन से है। शासन में शुचिता सर्वोपरि महत्त्व रखती है क्योंकि यह पारदर्शी, जवाबदेह और नैतिक रूप से मजबूत लोक प्रशासन के लिए आधार के रूप में कार्य करती है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के सिद्धांतों में निहित, शुचिता एक रूपरेखा स्थापित कर सरकारी संस्थानों के प्रभावी कामकाज को रेखांकित करती है।

शासन में शुचिता का महत्त्व

- निर्णय लेने में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को कायम रखना।
- सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देना।
- भ्रष्टाचार एवं अनैतिक आचरण को रोकना।
- प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाना।
- कानून और न्याय के शासन को मजबूत करना।
- सार्वजनिक मामलों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना।
- सरकारी संस्थानों की विश्वसनीयता बढ़ाना।
- जिम्मेदार और प्रभावी शासन के लिए नींव तैयार करना।
- सरकार की मंशा के प्रति सकारात्मक धारणा बनाना।

लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने में ईमानदारी की भूमिका:

- शुचिता के माध्यम से पारदर्शिता:
 - शुचिता पारदर्शी सार्वजनिक प्रशासन सुनिश्चित करती है। यह सिद्धांतों का पालन सरकारों को बजट, अनुबंध और नीतियों जैसी जानकारी को खुले तौर पर साझा करने के लिए मजबूर करती है। यह भ्रष्टाचार को रोकती है, विश्वास पैदा करती है और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करती है।
 - उदाहरण: भारत की डिजिटल इंडिया पहल डिजिटल इंडिया ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसे प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किए हैं। GeM नागरिकों को सरकारी खरीद पर डेटा के साथ सशक्त बनाता है, डिजिटल पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास को बढ़ावा देता है।
- जवाबदेही को बरकरार रखना:
 - शुचिता स्वाभाविक रूप से जवाबदेही की ओर ले जाती है। शुचिता के मानकों का पालन सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाता है, भ्रष्टाचार को रोकता है और सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता देता है।
 - उदाहरण: राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में धन का दुरुपयोग हुआ, जिससे जांच और कानूनी कार्रवाई हुई। यह दर्शाता है कि कैसे शुचिता जवाबदेही को लागू करती है, जनता के अविश्वास के परिणामों को सुनिश्चित करती है।

● नैतिक आचरण और शुचिता:

- शुचिता नैतिक मानदंडों को स्थापित करती है। नैतिकता को कायम रखना निष्पक्ष निर्णयों की गारंटी देता है, सरकारी कार्यों में जनता का विश्वास बढ़ाता है।
 - **उदाहरण:** भारत में हितों के टकराव के नियमों में वित्तीय हितों का खुलासा करने और स्व-लाभ वाले निर्णयों से बचने की मांग की गई है। यह समझौता किए गए निर्णयों को रोकने और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने में शुचिता की भूमिका को दर्शाता है।

शुचिता की लोक प्रशासन के निर्धारण में अन्य भूमिका

● नीति निर्माण और कार्यान्वयन:

- नैतिक विचार सामूहिक कल्याण के लिए नीतियों का मार्गदर्शन करना।
- निहित स्वार्थों के प्रभाव को रोकना, जैसा कि पर्यावरण नियमों में देखा गया है।

● संसाधनों का आवंटन:

- संसाधन आवंटन में नैतिक आचरण सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक धन के कुप्रबंधन को रोकना।
- भ्रष्टाचार और अपव्यय को कम करना।

● निर्णयन:

- जटिल निर्णयों के लिए नैतिक विचार महत्वपूर्ण हैं।
- विशेषकर महामारी जैसे संकट के दौरान सत्यनिष्ठा बनाए रखना।
- व्यक्तिगत हितों से अधिक अच्छे को प्राथमिकता देना।

● सेवा वितरण:

- शुचिता न्यायसंगत और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करती है।
- भेदभाव और पक्षपात को रोकना।
- रिश्वतखोरी और जबरन वसूली पर अंकुश लगाना, निष्पक्षता को बढ़ावा देना।

उदाहरण के तौर पर:

- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:** यह अधिनियम सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र लोकपाल के गठन का प्रावधान करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
- **राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2010:** भारत में राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से प्रशासन में शुचिता की कमी सामने आयी। इस घटना ने सार्वजनिक मामलों में नैतिक मानकों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया।
- **आधार कार्यान्वयन:** कार्यक्रम में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को संभालने में शुचिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था।
- **कोविड-19 राहत कोष:** कोविड-19 महामारी के दौरान, भ्रष्टाचार और राहत कोष के दुरुपयोग के मामलों ने आपातकालीन संसाधनों के वितरण में शुचिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह सुनिश्चित करने के लिए नैतिक आचरण आवश्यक था कि जरूरतमंद लोगों तक राहत तुरंत और निष्पक्ष रूप से पहुँचे।

लोक प्रशासन के लिए शासन में शुचिता महत्वपूर्ण है। यह एक उत्तरदायी शासन प्रणाली का निर्माण करती है जो कानून के शासन को कायम रखती है और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देती है। एक उचित एवं न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए शुचिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है और सभी स्तरों पर अधिकारियों के बीच मजबूत कानूनी ढाँचे और नैतिक व्यवहार की संस्कृति की आवश्यकता है।

13. लोक प्रशासन में नैतिक मार्गदर्शन के बाहरी स्रोतों के रूप में कानूनों, नियमों और विनियमों की भूमिका की चर्चा कीजिये। ये तंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में जवाबदेही, स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायता करते हैं? अपने उत्तर को ऐतिहासिक और समकालीन दोनों संदर्भों के प्रासंगिक उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द) 15

Discuss the role of laws, rules and regulations as external sources of ethical guidance in public administration. How do these mechanisms help in promoting accountability, consistency and transparency in the decision-making process? Illustrate your answer with relevant examples from both historical and contemporary contexts. (250 words) 15

उत्तर: नैतिक मार्गदर्शन के बाहरी स्रोतों के रूप में कानूनों, नियमों और विनियमों की भूमिका लोक प्रशासन के भीतर उत्तरदायी और सैद्धांतिक व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। ये तंत्र एक संरचित ढांचा प्रदान करते हैं जो जवाबदेही, स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय नैतिक मानकों के अनुरूप हों और निम्नलिखित तरीके से सार्वजनिक हित के लिये लाभप्रद हो-

जवाबदेही को बढ़ावा देना:

- कानून और विनियम एक कानूनी ढांचा स्थापित करते हैं जो लोक प्रशासकों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करे। वे अपने अधिकार की सीमाओं को परिभाषित करते हैं और कदाचार या लापरवाही के परिणामों को निर्दिष्ट करते हैं, जिससे जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
 - उदाहरण - 1980 के दशक में, एक रक्षा सौदे में कथित रिश्वत से जुड़े बोफोर्स घोटाले के कारण अधिक जवाबदेही की मांग उठी। इस घटना ने मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की आवश्यकता को प्रेरित किया और सार्वजनिक प्रशासकों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के महत्व को रेखांकित किया।
 - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल (लोकपाल) और राज्य-स्तरीय समकक्ष (लोकायुक्त) की स्थापना का प्रावधान किया। ये निकाय सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने, सार्वजनिक प्रशासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **एकरूपता सुनिश्चित करना:**
 - कानून और नियम एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करते हैं जो समान मामलों के साथ एक समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। यह स्थिरता मनमाने ढंग से निर्णय लेने के जोखिम को कम करती है और जनता का विश्वास बढ़ाती है।
 - 1954 में स्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) आचार संहिता उन सिद्धांतों को निर्धारित करती है जिनका आईएएस अधिकारियों से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यह कोड विभिन्न क्षेत्रों और विभागों में प्रशासकों के व्यवहार में स्थिरता सुनिश्चित करता है, निर्णय लेने में नैतिक आचरण को बढ़ावा देता है।
 - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम:** बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पूरे भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए समान मानक निर्धारित करता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को आधार बनाये बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिससे शैक्षिक अवसरों में निरंतरता को बढ़ावा मिले।

पारदर्शिता बढ़ाना:

कानून और विनियम जनता के सामने जानकारी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के प्रकटीकरण की आवश्यकता के द्वारा पारदर्शिता को अनिवार्य करते हैं।

● उदाहरण:

- 2005 में अधिनियमित सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम ने नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड और जानकारी तक पहुँचने में सक्षम बनाकर पारदर्शिता में बदलाव किया है, जिससे सार्वजनिक जागरूकता और जवाबदेही बढ़ी है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 कॉर्पोरेट प्रशासन में पारदर्शिता को अनिवार्य बनाता है। इसमें कंपनियों को व्यवसाय संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शेयरधारकों और जनता को वित्तीय जानकारी, कॉर्पोरेट नीतियों और कार्यकारी मुआवजे का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।

नैतिक मार्गदर्शन के ये बाहरी स्रोत निर्णय लेने में निष्पक्षता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देकर सार्वजनिक प्रशासन के ढाँचे को मजबूत करते हैं। वे सरकार के कार्यों में जनता के विश्वास को बढ़ावा देते हैं, सामान्य हितों को बढ़ाते हैं और राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान करते हैं।

14. जनमत को निर्धारित करने तथा निर्णयन में अनुनयन की भूमिका की जांच कीजिये। स्रोत की विश्वसनीयता, संदेश सामग्री और दर्शकों के विशिष्ट गुण जैसे कारक प्रेरक संचार की प्रभावशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? (250 शब्द) 15

Examine the role of persuasion in shaping public opinion and decision-making. How do factors such as source credibility, message content and audience characteristics influence the effectiveness of persuasive communication? (250 words) 15

उत्तर: अरस्तू ने अपने 'Rhetoric' नामक कार्य में प्रभावी संचार और तर्क के माध्यम से किसी के विश्वास, दृष्टिकोण, राय या व्यवहार को प्रभावित करने के एक कार्य के रूप में अनुनयन पर चर्चा की है।

अनुनयन की भूमिका:

अनुनयन की भूमिका दूसरों को एक विशेष दृष्टिकोण, विश्वास, राय या व्यवहार अपनाने के लिए प्रभावित करना और समझाना है। यह मानव संपर्क और संचार के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुनयन के पक्ष और विपक्ष:

- गुण:
 - प्रभावी संचार और संदेश वितरण
 - सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है।
 - कार्रवाई और निर्णय लेने को प्रेरित करता है।
 - बातचीत और संघर्ष समाधान की सुविधा प्रदान करता है।
 - शैक्षिक अनुभव और सहभागिता को बढ़ाता है।
- दोष:
 - अनैतिक रूप से उपयोग किए जाने पर नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
 - गलत सूचना और गलत धारणाएँ फैला सकते हैं।
 - गहन अभियान ध्रुवीकरण में योगदान दे सकते हैं।
 - विपरीत प्रभाव मौजूदा मान्यताओं को मजबूत कर सकता है।
 - सांस्कृतिक असंवेदनशीलता दर्शकों को नाराज कर सकती है।

अनुनयन का महत्त्व:

जनमत को निर्धारित करने और निर्णय लेने में अनुनयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें लोगों के विश्वासों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए संचार का उपयोग करना शामिल है।

- स्रोत विश्वसनीयता:
 - विशेषज्ञता: भारत में लोग अक्सर अधिकारियों और विशेषज्ञों का सम्मान करते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में एक प्रेरक संदेश तब अधिक प्रभावी होता है जब यह एक प्रसिद्ध भारतीय डॉक्टर द्वारा दिया जाता है जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है।

- स्वास्थ्य अभियान में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. देवी शेट्टी का समर्थन स्वास्थ्य संबंधी संदेश की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
- **उदाहरण:** भारत में, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता के कारण बॉलीवुड हस्तियों द्वारा उत्पादों का समर्थन आम बात है। उदाहरण के लिए, किसी सेलिब्रिटी द्वारा किसी कपड़े के ब्रांड का प्रचार करने से बिक्री बढ़ सकती है।
- **संदेश की सामग्री:**
 - **सांस्कृतिक प्रासंगिकता:** पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने वाला एक प्रेरक अभियान देश भर के लोगों से जुड़ने के लिए विविध सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग कर सकता है।
 - **उदाहरण:** कोका-कोला के “ठंडा मतलब कोका-कोला” अभियान ने भारतीयों की ताजा पेय की इच्छा को जोड़ने के लिए ठंडा की अवधारणा का चतुराई से उपयोग किया जाना, जिससे यह एक प्रतिष्ठित अभियान बन गया।
- **श्रोता के गुण:**
 - **धार्मिक मान्यताएँ:** भारत की धार्मिक विविधता प्रेरक संदेशों को प्रभावित करती है। स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देते समय, प्रकृति के प्रति श्रद्धा की हिंदू अवधारणाओं पर विचार करने से संदेश अधिक प्रभावशाली बन सकता है।
 - **उदाहरण:** स्वच्छ भारत अभियान दर्शकों के स्वच्छ देश के गौरव पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे स्वच्छता के सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ता है।
- **संदेश निर्धारण:**
 - **सकारात्मक निर्धारण:** सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लाभों को बढ़ावा देने वाला एक अभियान यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने पर जोर दे सकता है।
 - **नकारात्मक निर्धारण:** स्वास्थ्य जोखिमों के संदर्भ में तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में बताना सरकार के धूम्रपान विरोधी प्रयासों के अनुरूप है।
 - **उदाहरण:** “नमामि गंगे” परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी को साफ करना है और इसे सांस्कृतिक भावनाओं के अनुरूप एक पवित्र नदी की बहाली के रूप में सकारात्मक रूप से तैयार किया गया है।
- **संज्ञानात्मक और भावनात्मक कारक:**
 - **संज्ञानात्मक संगति:** एक प्रेरक संदेश जो पहले से मौजूद मान्यताओं के साथ संरेखित होता है, जैसे कि पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा देना, अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिध्वनित हो सकता है।
 - **भावनात्मक प्रभाव:** प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के बारे में भावनात्मक कहानियाँ भारत में गहराई से प्रतिध्वनित हो सकती हैं, जैसा कि व्यक्तियों की गरीबी से अमीरी तक की यात्रा को प्रस्तुत करने वाले अभियानों में देखा गया है।
 - **उदाहरण:** “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान लैंगिक असमानता को संबोधित करते हुए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देते हुए भावनाओं पर आधारित है।
- **संदर्भ और समय:**
 - **त्यौहार और उत्सव:** दिवाली या ईद जैसे प्रमुख त्यौहारों के साथ समय पर अभियान चलाने से बेहतर जुड़ाव हो सकता है। दिवाली के दौरान पर्यावरण-अनुकूल उत्सवों को बढ़ावा देने वाला एक अभियान प्रदूषण के बारे में चल रही वार्ता के अनुरूप है।
 - **राष्ट्रीय मुद्दे:** डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने वाला एक प्रेरक संदेश डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर भारत के प्रयास के अनुरूप है।
 - **उदाहरण:** होली के दौरान, जल प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल रंगों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले अभियानों द्वारा प्रगति और जागरूकता प्राप्त करना।

भारत में जनमत को निर्धारित करने तथा निर्णय लेने में स्रोत की विश्वसनीयता, संदेश सामग्री और दर्शकों विशिष्ट गुणोंओं की बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण है। भारतीय संदर्भ के अद्वितीय सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं के अनुरूप प्रेरक संचार को तैयार करके, संचारक अभिवृत्ति और व्यवहार को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं।

15. एक दिन काशगंज शहर में एक स्थानीय दूधवाला दो पुलिसकर्मियों और दो नागरिकों के साथ उस वार्ड में आया, जहां वह घर-घर दूध की आपूर्ति के लिए रोजाना जाता था। वह वार्ड के अधिकतर रहवासियों से एक अलग धर्म को मानता है। उसने पुलिसकर्मियों को बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी लापता है उसे संदेह है कि इसी वार्ड का एक व्यक्ति X इसमें शामिल है। पुलिस ने X के घर की जांच की और उसे, यह कहते हुए कि वे पूछताछ के बाद उसे छोड़ देंगे, साथ ले गए। X की मां Y ने कहा कि जब पुलिस X को ले गई तो दूधवाले ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उनके बेटे का गला काट दिया जाएगा। शाम लगभग 5 बजे, श्री Z (X के पिता) को एक व्यक्ति ने सूचित किया कि X की हालत ठीक नहीं है और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया है। जब परिजन वहां पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि X की मौत हो गई है और उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है। जब श्री Z, उनकी पत्नी Y और कुछ अन्य लोग जिला अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें शवगृह में शव दिखाया गया। श्री Z ने अपने बेटे X की हिरासत में मौत के लिए पुलिस को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उनसे लगभग रात्रि 1 बजे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे और पुलिस द्वारा एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वह जांच से संतुष्ट हैं। तीन वर्ष पूर्व X के खिलाफ नोएडा में एक कार, जिसे वह खुद चला रहे थे, से दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद मामला दर्ज किया गया था। तब वह नाबालिग थे। पुलिस अधिकारियों ने श्री Z से कहा (जैसा कि श्री Z ने दावा किया है) कि वे दुर्घटना से संबंधित मामले को भी सुलझा लेंगे। इसके बदले में पुलिस ने श्री Z को उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जिसमें लिखा था कि X ने “अवसाद में” स्वयं अपनी जान ले ली है और उसे पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है तथा वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, X ने अपनी जैकेट की नायलॉन कसने वाली रिंग का इस्तेमाल किया और शौचालय के अंदर लेट गया। यह भी पाया गया कि मजिस्ट्रेट को थाने के अंदर नहीं बुलाया गया था। जब X को लाया गया तो दैनिक डायरी में प्रविष्टि नहीं की गई थी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दूधवाला फरार है और लड़की का अभी तक पता नहीं चला है। चुनाव करीब होने के कारण यह मुद्दा राज्य की राजनीति में तूल पकड़ता जा रहा है। काशगंज से पुलिस अधीक्षक के रूप में: (250 शब्द) 20

- (a) आपके पास कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?
 (b) आप किस विकल्प पर विचार करेंगे और क्यों?
 (c) आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि निष्पक्ष जांच, सार्वजनिक विश्वास आदि जैसे विभिन्न नैतिक मुद्दे प्रबल हों?

One day a local milkman in Kashganj town came with two policemen and two civilians into the ward he used to visit daily for door to door milk supply. He belongs to a different religion that the most resident of the ward. He told policemen that his daughter, 16, had been missing and he suspected a person X who is from this ward, was involved in it. The police checked X's house and took his saying they will release him after questioning. X's mother Y said the milkman had threatened them when the police took X saying their son's throat would be slit if he did not tell the truth. Around 5 p.m., Mr. Z (X's Father) was informed by a villager that X was not well and was admitted to the community healthcare centre. When the family rushed there, they were informed that X was dead and taken to the district hospital. When Mr. Z, his wife Y and a few others reached the district hospital, they were shown the body in the mortuary. Mr. Z blamed the police for the custodial death of his son X. He said that he was made to sign the documents around 1a.m. and a video was also recorded by police in which he said he was satisfied with the investigation. There was a case registered against X in Noida three years ago following the death of a person in an accident by the car he was driving. He was a minor then. The police officials told Mr. Z (as claimed by Mr. Z) that they will settle that case as well. In lieu of that Police said Mr. Z to sign the document in which it was written that X had taken his life

“in depression” and that he has no complaints against the police and that he didn’t wish to pursue the matter. According to police sources, X used his jacket’s nylon tightening ring and lay down inside the toilet. It was also found that the magistrate was not called inside the police station. The daily diary entry was not made when X was brought in. Police sources said the milkman was absconding and the girl was yet to be traced. This issue is getting inroad to state politics as the election is round the clock. As an Superintendent of Police from Kashganj: (250 words) 20

(a) What are the options you have?

(b) Which option will you consider and why?

(c) How would you ensure the various ethical issues prevail such as impartial investigation, public trust etc?

उत्तर: गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार 2021-2022 के दौरान देश में हिरासत में मौत के 175 मामले थे।

काशगंज के पुलिस अधीक्षक के रूप में, यह स्थिति एक जटिल और संवेदनशील चुनौती प्रस्तुत करती है जिसके लिए नैतिक मानकों और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के दौरान विभिन्न विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

(a)

- मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच के आदेश देना। यह कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकारियों की एक टीम द्वारा किया जाना चाहिए। जांच पूरी तरह से होनी चाहिए और इसमें सभी संभावित दृष्टिकोणों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें पुलिस द्वारा धोखाधड़ी की संभावना भी शामिल है।
- X की मौत में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करना। इस मामले की जांच CID या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए।
- X की मौत में शामिल पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश देना। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वे जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
- X के परिवार से मिलना और उन्हें अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करना। उन्हें यह भी आश्वासन देना कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे।
- भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए कदम उठाना। इसमें पुलिस अधिकारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण, पुलिस गतिविधियों की कड़ी निगरानी और पुलिस अधिकारियों के लिए अधिक जवाबदेही जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।

(b)

मैं जिस विकल्प पर विचार करूँगा वह X की मौत की निष्पक्ष जांच का आदेश देना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सच्चाई को सामने लाना और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि। मैं जांच के नतीजे आने तक X की मौत में शामिल पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दूँगा।

(c)

नैतिक प्रतिपूर्ति:

- **निष्पक्ष जांच:** चुने गए विकल्प में पुलिस अधिकारियों सहित इसमें शामिल सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हुए निष्पक्ष जांच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **सार्वजनिक विश्वास:** पारदर्शिता, खुला संचार और समुदाय के साथ सहयोग से पुलिस बल में जनता के विश्वास को फिर से बनाने और बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- **निर्दोषता की धारणा:** दोषी साबित होने तक सभी संदिग्धों को निर्दोष मानना। इस सिद्धांत को जांच और उसके बाद की कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

- **मानवाधिकार:** सुनिश्चित करना कि सभी कार्य और प्रक्रियाएं व्यक्तियों के मानवाधिकारों का सम्मान करें, चाहे वे संदिग्ध हों या पीड़ित।
- **न्याय:** संपूर्ण जांच करके और किसी भी प्रक्रियात्मक या कानूनी उल्लंघन का समाधान करके न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना।
- **सत्यनिष्ठा:** किसी भी गलत काम के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराकर और सुधारात्मक उपाय करके पुलिस बल की सत्यनिष्ठा बनाए रखना।

निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना

- **प्रक्रियात्मक भूल का समाधान:**
 - पुलिस प्रक्रियाओं की आंतरिक समीक्षा करना, जिसमें मजिस्ट्रेट को शामिल करने में विफलता और X की हिरासत के दौरान दैनिक डायरी प्रविष्टि की अनुपस्थिति शामिल है।
 - भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक खामियों को सुधारना और उचित गिरफ्तारी तथा हिरासत प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना:**
 - जनता, सामुदायिक नेताओं और स्थानीय मीडिया आउटलेट्स को नियमित अपडेट प्रदान करके जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
 - उचित प्रक्रियाओं की उपेक्षा, जबरदस्ती व्यवहार या X की हिरासत से संबंधित किसी भी कदाचार के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को जवाबदेह ठहराना।
- **बाहरी एजेंसियों के साथ सहयोग करना:**
 - जांच की निगरानी करने और इसकी न्यायसंगतता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी एजेंसियों जैसे मानवाधिकार संगठनों या कानूनी विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना।

लोगों का विश्वास

- **पीड़ित परिवार का सहयोग करना:**
 - इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान X के परिवार को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
 - परिवार की चिंताओं को दूर करने और जांच की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उन्हें संचार की सुविधा प्रदान करना।
 - **समुदाय के साथ जुड़ाव:**
 - चिंताओं को दूर करने, अपडेट प्रदान करने और कानून प्रवर्तन में विश्वास बनाने के लिए सामुदायिक नेताओं, स्थानीय प्रतिनिधियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ जुड़ना।
 - **राज्य की राजनीति से तटस्थता बनाए रखना:**
 - सुनिश्चित करें कि जांच और की गई कार्रवाई राज्य में चल रही राजनीति या आगामी चुनाव से प्रभावित न हो। राजनीतिक विचारों से ऊपर न्याय और नैतिक मानकों को बनाए रखने पर ध्यान देना।
 - **समय पर शव परीक्षण (Autopsy) और दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना:**
 - मौत का कारण सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए X के शरीर का संपूर्ण शव परीक्षण करवाना।
 - पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए जांच के सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण बनाए रखना।
- जटिल स्थिति में संतुलित और नैतिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, सामुदायिक नेताओं और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के परामर्श से इनमें से प्रत्येक विकल्प पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अंतिम लक्ष्य न्याय को कायम रखना, जनता का विश्वास बहाल करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना होना चाहिये।

16. आप एक प्रबंधक हैं जो शिविका नामक कर्मचारी को प्रबंधित कर रहे हैं। समय के साथ, व्यक्तिगत मुद्दों के कारण शिविका के कार्य प्रदर्शन में गिरावट आने लगी। उन्हें कार्य को समय सीमा को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके काम की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इन चिंताओं को दूर करने के लिए आपने उनसे कई बार बातचीत की। जैसे-जैसे समय बीतता गया, उसकी उपस्थिति विसंगत होती गई, तथा पता चला है कि वह भावनात्मक कठिनाइयों से जूझ रही है।

एक निश्चित बिंदु पर, शिविका ने आपसे संपर्क किया और बताया कि वह महत्वपूर्ण पारिवारिक मुद्दों से निपट रही है, जिस पर उसे पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपने उसके अनुरोध को मंजूरी दे दी, जिससे उसे अपने पारिवारिक मामलों पर ध्यान देने के लिए आवश्यक समय मिल गया।

उनकी अनुपस्थिति के दौरान, टीम को शिविका के कार्यभार का पुनर्वितरण करना पड़ा, जिसने कई चुनौतियों को प्रस्तुत किया। इसके बावजूद, टीम परिचालन दक्षता बनाए रखने में कामयाब रही। जब शिविका अंततः काम पर लौटीं, तो उनके प्रदर्शन में विसंगतियां बनी रहीं, जिससे पता चला कि उनके व्यक्तिगत मुद्दे अभी भी उनके काम को प्रभावित कर रहे हैं।

कई महीनों के बाद, आपको शिविका को उसके प्रदर्शन संबंधी मुद्दों के कारण उसे कंपनी से बाहर करने के चुनौतीपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ा। ये मुद्दे टीम के कामकाज और कंपनी के व्यापक उद्देश्य दोनों को प्रभावित कर रहे थे। एक निष्कपट बातचीत में, आपने उसे समझाया कि निर्णय उसके प्रदर्शन और परिचालन आवश्यकताओं पर आधारित था।

शिविका के जाने के कुछ महीने बाद, आपको उससे से एक ईमेल प्राप्त हुआ। उसने आपको एक अन्य कंपनी में नौकरी के आवेदन के बारे में कहा और बताया कि उसने आपको संदर्भ के रूप में सूचीबद्ध किया है। उन्होंने अपनी बेहतर मानसिक स्थिति और अपनी पिछली चुनौतियों से सीखे गए सबक के बारे में बताया। एक विनम्र अनुरोध में, उन्होंने आपसे एक सकारात्मक संदर्भ प्रदान करने के लिए कहा, जिसमें आपके कंपनी में रहने के दौरान उनके द्वारा सामना की जाने वाली व्यक्तिगत कठिनाइयों का कोई उल्लेख न करते हुए उनके समर्पण और कौशल पर जोर दिया गया हो।

जबकि आप शिविका की स्थिति के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं और उपयुक्त परिस्थितियों में एक मूल्यवान योगदानकर्ता के रूप में उसकी क्षमता को पहचानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि उसके प्रदर्शन संघर्षों का टीम की उत्पादकता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। (250 शब्द) 20

इस स्थिति को देखते हुए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

- (a) शिविका को एक कर्मचारी के लिए संदर्भ प्रदान करते समय प्रबंधक के रूप में आप किन नैतिक विचारों को ध्यान में रखेंगे, जो व्यक्तिगत मामलों से संबंधित प्रदर्शन के मुद्दों से जूझ रहे थे, साथ ही नए रोजगार हासिल करने की व्यक्तिगत संभावनाओं का समर्थन करना चाहते हैं?
- (b) ऐसे उदाहरणों में जहां व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण किसी कर्मचारी की कार्य गुणवत्ता और उपस्थिति में गिरावट आती है, प्रबंधक इन चुनौतियों को अप्रबंधनीय होने से पहले सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए क्या कदम उठा सकता है?

You are a manager overseeing an employee named Shivika. Over time, Shivika's job performance began to decline due to personal issues. She faced challenges in meeting deadlines, and the quality of her work suffered. You had multiple conversations with her to address these concerns. As time went on, her attendance became inconsistent, suggesting that she was dealing with emotional difficulties.

At a certain point, Shivika approached you and explained that she was dealing with significant family issues that required her full attention. Considering her situation, you approved her request, allowing her the time she needed to tend to her family matters.



During her absence, the team had to redistribute Shivika's workload, which presented its own set of challenges. Despite this, they managed to maintain operational efficiency. When Shivika eventually returned to work, her performance inconsistencies persisted, indicating that her personal struggles continued to impact her job focus.

After several months, you faced the challenging decision of letting Shivika's go due to her ongoing performance issues. These issues were affecting both the team's functioning and the company's broader objectives. In an honest conversation, you explained to her that the decision was based on her performance and the operational necessities.

A few months after her departure, you received an email from Shivika. She informed you about her job application at a different company and mentioned that she had listed you as a reference. She conveyed her improved state of mind and the lessons she had learned from her past challenges. In a humble request, she asked you to provide a positive reference, emphasizing her dedication and skills while excluding any mention of the personal difficulties she faced during her time at your company.

While you deeply empathize with Shivika's situation and recognize her potential as a valuable contributor in suitable circumstances, you are also aware that her performance struggles had a notable impact on the team's productivity. (250 words) 20

Given this situation, answer the following questions

- (a) What ethical considerations would you take as manager into account when providing a reference for a Shivika employee who struggled with performance issues related to personal matters, while also wanting to support the individual's chances of securing new employment?
- (b) In instances where an employee's work quality and attendance decline due to personal difficulties, what steps could a manager take to proactively address these challenges before they become unmanageable?

उत्तर:

(a)

शिविका जैसी कर्मचारी, जिसे अपनी नौकरी के दौरान व्यक्तिगत मामलों के कारण प्रदर्शन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, के लिए संदर्भ देते करते समय, मैं निम्नलिखित नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखूँगा:

- **सत्यता और सटीकता:** मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि संदर्भ में शिविका के प्रदर्शन, उसकी ताकत और उसके सामने आने वाली चुनौतियों, दोनों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित किया जाए। नैतिक सत्यनिष्ठा की मांग है कि साझा की गई जानकारी सत्य हो तथा भ्रामक न हो।
- **संतुलित मूल्यांकन:** मैं एक संतुलित मूल्यांकन करने का प्रयास करूँगा जो निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए उसके सकारात्मक योगदान और सामने आने वाली कठिनाइयों दोनों को प्रस्तुत करता हो।
- **सूचित सहमति:** मैं किसी भी संदर्भ जानकारी को साझा करने से पहले शिविका की सहमति के अधिकार का सम्मान करते हुए उससे अनुमति लूँगा।
- **गोपनीयता और निजता:** मैं केवल प्रासंगिक जानकारी, जिसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, साझा करके शिविका की गोपनीयता का सम्मान करूँगा।
- **पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता:** मैं संदर्भ में किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को शामिल किए बिना शिविका की क्षमताओं के प्रति एक पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करूँगा।
- **प्रभाव आकलन:** संदर्भ के प्रभाव का आकलन करते समय, मैं सटीकता बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी के साथ-साथ शिविका के करियर के संभावित लाभ पर भी विचार करूँगा।



641, प्रथम तल,
मुखर्जी नगर,
दिल्ली

21, पूसा रोड,
करोल बाग,
नई दिल्ली

13/15, ताशकंद मार्ग,
निकट पत्रिका चौराहा,
सिविल लाइन्स, प्रयागराज

1st & 2nd Floor, No-47/CC,
बर्लिंगटन आर्केड मॉल,
विधानसभा मार्ग, लखनऊ

प्लॉट नंबर-45 व 45-A
हर्ष टावर-2, मेन टॉक रोड,
वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर

31

दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 :: ई-मेल: help@groupdrishti.in :: वेबसाइट: www.drishtiIAS.com

- **व्यावसायिक विकास का मूल्य:** मैं उन प्रयासों पर जोर दूंगा जो शिक्का ने चुनौतियों का सामना करने और पेशेवर रूप से आगे बढ़ने के लिए किए हैं, जो मानना है कि मेरा नए रोजगार को सुरक्षित करने के लिए नैतिक रूप से उसके अवसरों को बढ़ा सकता है।

(b)

जब किसी कर्मचारी की कार्य गुणवत्ता और उपस्थिति व्यक्तिगत कठिनाइयों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, तो एक प्रबंधक इन चुनौतियों को अप्रबंधनीय होने से पहले उनका समाधान करने के लिए निम्नलिखित सक्रिय कदम उठा सकता है:

- **खुला संचार:** चिंता व्यक्त करने के लिए कर्मचारी के साथ एक व्यक्तिगत बातचीत शुरू करना और उनकी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित परिवेश निर्मित करना। उन्हें उनके प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्तिगत मुद्दे को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **सक्रिय श्रवण:** कर्मचारी द्वारा सामना की जा रही व्यक्तिगत कठिनाइयों की विशिष्ट प्रकृति को समझने के लिए सक्रिय होकर सुनने का प्रयास करना। इससे सहानुभूति रखने और संभावित समाधानों की पहचान करने में मदद मिलती है।
- **अनुकूल कार्य दशाएँ:** उनकी व्यक्तिगत स्थिति को समायोजित करने के लिए उनके कार्य शेड्यूल या कार्यभार में अस्थायी समायोजन की संभावना पर चर्चा करना। अनुकूल व्यवस्थाएँ तत्काल तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं।
- **संसाधन प्रदान करना:** उपलब्ध संसाधनों, जैसे परामर्श सेवाओं या कर्मचारी सहायता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना, जो कर्मचारी की व्यक्तिगत चुनौतियों के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- **लक्ष्य निर्धारण:** कर्मचारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके साथ सहयोगात्मक रूप से स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करना। ये लक्ष्य प्राप्त करने योग्य तथा संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए।
- **नियमित जाँच:** चल रहे कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित रूप से बैठकें करना। सुधारों का आकलन करने और किसी भी उभरती चुनौती का समाधान करने के लिए संवाद करना।
- **प्रशिक्षण या सुधार की पेशकश करना:** यदि उपयुक्त हो, तो प्रशिक्षण या कौशल विकास के अवसर प्रदान करना जो कर्मचारी को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और उनकी भूमिका में अधिक आत्मविश्वास महसूस कराने में मदद कर सके।
- **कार्य सौंपना तथा पुनर्वितरित करना:** यदि व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण कर्मचारी का कार्यभार अत्यधिक है, तो उनके बोझ को कम करने के लिए टीम के अन्य सदस्यों को कुछ कार्य सौंपने पर विचार करना।
- **गोपनीयता बनाए रखना:** यह सुनिश्चित करके कि, साझा की गई कोई भी व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाए, कर्मचारी की निजता का सम्मान करना। यह नकारात्मक परिणामों के डर के बिना खुले संचार को प्रोत्साहित करता है।
- **खुद की देखभाल को प्रोत्साहित करना:** आत्म-देखभाल और कल्याण के महत्त्व पर जोर देना। कर्मचारी को अवकाश लेने, तनाव का प्रबंधन करने और उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **मानव संसाधन मार्गदर्शन लेना:** यदि व्यक्तिगत कठिनाइयाँ जटिल हैं या संभावित रूप से कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, तो उचित समाधान तलाशने के लिए मानव संसाधन विभाग को शामिल करना।
- **प्रगति की निगरानी करना:** लक्ष्यों को पूरा करने और चुनौतियों को नियंत्रित करने की दिशा में कर्मचारी की प्रगति का नियमित मूल्यांकन करना। रणनीतियों को उनके विकास के आधार पर आवश्यकतानुसार समायोजित करना।
- **सहायक संस्कृति को बढ़ावा देना:** कार्यस्थल पर ऐसे माहौल को बढ़ावा देना जहां कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों को साझा करने तथा बिना किसी भय के मदद मांगने में सहज महसूस करें।

इन सक्रिय कदमों को उठाकर, प्रबंधक एक सहायक और समझदार कार्य परिवेश निर्मित कर सकते हैं जो कर्मचारियों को उनकी कार्य जिम्मेदारियों को बनाए रखते हुए उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों का प्रबंधन करने में मदद करता है।

17. आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो एक महत्वपूर्ण कोडिंग कार्य पर काम कर रहे हैं जिसे दिन के अंत तक पूरा करना है। जैसे ही आप कार्यालय में कोड की अंतिम कार्य को समाप्त करने की ओर हैं, आपको अपने वृद्ध पड़ोसी की एक आवश्यक कॉल आती है। वह अपने घर में सीढ़ियों से गिर गई हैं और बेहद दर्द से जूझ रही हैं। वह अकेली रहती हैं और उसकी मदद के लिए आस-पास कोई परिवार नहीं है। वह अस्पताल पहुंचने में आपकी सहायता की गुहार लगाती है। अपने पड़ोसी की सहायता की तत्काल आवश्यकता के साथ अपने व्यावसायिक दायित्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हुए, आप तेजी से कार्यालय छोड़ने और सहायता प्रदान करने का विकल्प चुनते हैं। उसके घर जाते समय, आपको एहसास होता है कि आपने संवेदनशील क्लाउंट जानकारी वाला अपना लैपटॉप अपने टेबल पर चालू अवस्था में छोड़ दिया है। यह जानकारी आपके कार्यालय में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जैसे ही आप अपने पड़ोसी के घर में कदम रखते हैं, उसे असहनीय दर्द और संकट में देखना एक गंभीर संदेश देता है कि - उनका जीवन गंभीर संकट में है और आपकी कार्यवाही यह निर्धारित करेगी। कि वह जीवित रहेगी या नहीं। इसी बीच, आपके पास कोडिंग कार्य पर मार्गदर्शन मांगने वाले सहकर्मियों के संदेश बहुतायत में प्राप्त होते हैं। घड़ी की सुई आगे बढ़ने के साथ तात्कालिकता की तीव्रता को बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही क्लाउंट का ईमेल प्राप्त होता है - आपके लैपटॉप पर संवेदनशील फाइलें उजागर हो गई हैं जिससे वे सुरक्षा उल्लंघन के बारे में चिंतित हैं।

इसी बीच, आपको अपनी टीम के एक साथी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फोन आता है। वे आपको सूचित करते हैं कि आप जिस कोडिंग कार्य पर कार्य कर रहे थे, उसमें एक महत्वपूर्ण बग (त्रुटि) पाया गया है। संभावित सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। स्थिति की तात्कालिकता तब बढ़ जाती है जब आपको एहसास होता है कि बग न केवल परियोजना को प्रभावित कर सकता है बल्कि क्लाउंट के संचालन को भी प्रभावित कर सकता है। (250 शब्द) 20

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए

(a) इस परिदृश्य में आप क्या करेंगे? और क्यों?

(b) सहकर्मियों, क्लाउंट और टीम के सदस्यों के साथ प्रभावी संचार व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्राथमिकताओं की प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं के प्रबंधन में कैसे योगदान देता है?

You are a software engineer working on a critical coding task that needs to be completed by the end of the day. As you're finalizing the last lines of code in the office, you receive an urgent call from your elderly neighbour. She has fallen down the stairs at her home and is in excruciating pain. She lives alone and has no immediate family nearby to help her. She pleads for your assistance in getting to the hospital. Struggling to reconcile your professional obligations with your neighbour's pressing need for assistance, you swiftly opt to leave the office and provide help. On your way to her house, you realize that you left behind your laptop with sensitive client data open on your desk. This information could be accessed by anyone who enters your office. As you step into your neighbour's home, the sight of her in excruciating pain and distress sends a stark message—her life hangs by a thread, and your actions could determine whether she survives or not. Meanwhile, colleagues flood you with messages seeking guidance on the coding task. The clock ticks down, intensifying the urgency. Simultaneously, the client email appears - sensitive files were exposed on your laptop, due to which they're alarmed about a security breach.

In the midst of this, you receive a call from a fellow software engineer on your team. They inform you that a critical bug has been discovered in the coding task you were working on. It requires your immediate attention to avoid a potential system crash. The urgency of the situation amplifies as you realize that the bug could impact not only the project but also the client's operations.

(250 words) 20



Given this situation, answer the following questions

(a) In this scenario what will you do? And why?

(b) How does effective communication with colleagues, clients, and team members contribute to managing ethical dilemmas that arise from competing personal and professional priorities?

उत्तर:

(a)

इस परिदृश्य में, मैं निम्नलिखित कार्रवाई करूँगा:

- **पड़ोसी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना:** मेरे पड़ोसी की स्थिति की गंभीर प्रकृति, जहाँ उसका जीवन अधर में लटका हुआ है, को देखते हुए मेरी तत्काल प्राथमिकता सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे आवश्यक चिकित्सा सहायता मिले। मानव जीवन को प्राथमिकता देकर मैं उसके जीवन को बचाने हेतु मदद करने के लिए एक मजबूत नैतिक दायित्व का पालन करूँगा।
- **संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखना:** संवेदनशील क्लाइंट डेटा से युक्त लैपटॉप को टेबल पर खुला छोड़ना एक चिंता का विषय है साथ ही मेरे पड़ोसी की स्थिति की गंभीरता पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं गोपनीय जानकारी तक अनधिकृत पहुँच के जोखिम को कम करने के लिए अपने लैपटॉप को दूरस्थ रूप से या भौतिक रूप से सुरक्षित करने के लिए किसी विश्वसनीय सहयोगी या कंपनी के आईटी विभाग से संपर्क करूँगा।
- **टीम के साथ संवाद करना:** मैं गंभीर परिस्थितियों और अपनी अस्थायी अनुपलब्धता की जानकारी देते हुए तुरंत अपनी टीम को स्थिति के बारे में सूचित करूँगा। ऐसे परिदृश्यों में प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है तथा मैं कोडिंग कार्य और किसी भी जरूरी मामले के प्रबंधन में उनकी समझ और सहयोग मांगूँगा।
- **बग के समाधान हेतु सहयोग करना:** महत्वपूर्ण बग के बारे में कॉल प्राप्त होने पर, मैं बग की गंभीरता और प्रभाव का आकलन करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर सहयोग करूँगा। हालाँकि मेरी प्राथमिकता अपने पड़ोसी की देखभाल करना और उनकी सकुशलता सुनिश्चित करना है, मैं जल्द से जल्द इस समस्या से निपटने की योजना पर काम करूँगा।
- **क्लाइंट की चिंता का जवाब देना:** क्लाइंट के सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित ईमेल के संबंध में, मैं ईमानदारीपूर्वक और तुरंत जवाब दूँगा। मैं भूल को स्वीकार करूँगा, किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करूँगा और उन्हें आश्वस्त करूँगा कि डेटा को सुरक्षित करने और अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जा रहे हैं।
- **सतत निगरानी:** अपने पड़ोसी का समर्थन करते हुए और कोडिंग कार्य को प्रबंधित करते हुए, मैं दोनों मोर्चों पर मौजूद रहने के लिए संचार चैनल खुले रखूँगा। एक बार जब मेरे पड़ोसी की हालत स्थिर हो जाएगी और बग का समाधान हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो मैं शेष कार्य को निपटाने के लिए कार्यालय लौटूँगा।

मेरे निर्णय नैतिक विचारों, मेरे पड़ोसियों की सकुशलता के लिए करुणा, मेरे पेशेवर कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी, सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ प्रभावी संचार और व्यावसायिकता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जरूरी मामलों को संतुलित करने के उद्देश्य से प्रेरित होंगे।

(b)

सहकर्मियों, ग्राहकों और टीम के सदस्यों के साथ प्रभावी संचार व्यक्तिगत और व्यावसायिक दायित्वों के बीच संघर्ष से उत्पन्न नैतिक दुविधाओं की जटिल उलझन को चतुराई से सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

● **समन्वित परिप्रेक्ष्य:**

- संचार एक जुड़ाव बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो हितधारकों के विविध दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करता है।
- दुविधा की जटिलताओं को साझा करने से एक व्यापक समझ सामने आती है जो संतुलित निर्णयों की जानकारी प्रस्तुत करती है।



641, प्रथम तल,
मुखर्जी नगर,
दिल्ली

21, पूसा रोड,
करोल बाग,
नई दिल्ली

13/15, ताशकंद मार्ग,
निकट पत्रिका चौराहा,
सिविल लाइन्स, प्रयागराज

1st & 2nd Floor, No-47/CC,
बर्लिंगटन आर्कैड मॉल,
विधानसभा मार्ग, लखनऊ

प्लॉट नंबर-45 व 45-A
हर्ष टावर-2, मेन टॉक रोड,
वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर

34

दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 :: ई-मेल: help@groupdrishti.in :: वेबसाइट: www.drishtiIAS.com

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- **सहानुभूति विकसित करना:**
 - आख्यान के माध्यम से, सहकर्मी, ग्राहक और टीम के सदस्य भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, स्थिति की गंभीरता को पहचानते हैं और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं।
- **सहयोगात्मक समाधान तैयार करना:**
 - संवाद से सहयोग उत्पन्न होता है। प्रत्येक बातचीत ऐसे समाधान तैयार करने में योगदान देती है जो सामूहिक समस्या-समाधान के सार को मूर्त रूप देते हुए पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ व्यक्तिगत तात्कालिकताओं को संतुलित करता है।
- **प्राथमिकताओं की स्पष्टता:**
 - पारदर्शी बातचीत प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालती है। हितधारक प्रतिबद्धता के मूल्य को समझते हैं, जिससे व्यक्तिगत कल्याण और पेशेवर सत्यनिष्ठा दोनों का सम्मान करने वाले निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- **अनुकूलनशीलता और लचीलापन:**
 - प्रभावी संचार अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करता है। जब सहकर्मी और ग्राहक दुविधा के संदर्भ को समझते हैं, तो वे लचीलेपन की पेशकश करने की अधिक संभावना रखते हैं जो दोहरे दायित्वों के तनाव को कम करता है।
- **नैतिक विकल्पों का मार्गदर्शन:**
 - नैतिक मुद्दे यह हर किसी को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सही है।
 - इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने से हर कोई नियमों का पालन करने वाले और ईमानदारी दिखाने वाले निर्णय लेने के लिए मिलकर काम करता है।
- **सूचित निर्णय लेना:**
 - दुविधा को साझा करने से विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ निर्णय लेने की क्षमता समृद्ध होती है, जिससे मूल्यों और जिम्मेदारियों का सम्मान करने वाली कार्रवाई की सुविधा मिलती है।
- **समर्थन नेटवर्क को बढ़ावा देना:**
 - आख्यान समर्थन पैदा करते हैं। जैसे ही सहकर्मी, ग्राहक और टीम के सदस्य नाजुक संतुलन को समझते हैं, एक समर्थन नेटवर्क निर्मित होता है, जो प्रतिस्पर्द्धी मांगों के दबाव को कम करता है।
- **नकारात्मक परिणामों को कम करना:**
 - पारदर्शी संवाद अनपेक्षित परिणामों को कम करता है।
 - जब हितधारकों को सूचित किया जाता है, तो वे पेशेवर स्थितियों में व्यवधानों को टालते हुए अपेक्षाओं और समयसीमा को समायोजित कर सकते हैं।
- **विश्वास निर्माण:**
 - चुनौतियाँ साझा करने से विश्वास मजबूत होता है। नैतिक दुविधाओं के बारे में खुलापन विश्वास पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देता है, जहां सहकर्मी और ग्राहक ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता को पहचानते हैं।